



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 25, 2016/वैशाख 5, 1938

No. 146]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 25, 2016/VAISAKHA 5, 1938

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 12 अप्रैल 2016

सं. टीएएमपी/54/2015-वीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, ईक्यू-7 में संस्थापित रेडियोलॉजिकल उपकरण के लिए प्रभारों के निर्धारण हेतु विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/54/2015-वीपीटी

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास

आवेदक

कोरम:

- (i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री रजत सचर, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(मार्च 2016 के 30 वें दिन पारित)

यह मामला ईक्यू-7 गेट में संस्थापित रेडियोलॉजिकल उपकरण सुविधा हेतु प्रभारों के निर्धारण के लिए विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 4 जुलाई 2015 से संबंधित है।

2.1. वीपीटी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की मुख्य बातों को नीचे सारबद्ध किया गया है:

- (i) विशाखापत्तनम पत्तन ने गोदी क्षेत्र परिसर के भीतर ईक्यू-7 में रेडियोलॉजिकल का पता लगाने के लिए अभियांत्रिक सुविधा (उपकरण) संस्थापित किया है, जिसमें उपर्युक्त स्थान में प्रवेश/निकासी प्वाइंट के माध्यम से गोदी क्षेत्र में आने और जाने वाले वाहनों की रेडियोलॉजिकल तत्व, यदि कोई हो, जोकि जोखिमपूर्ण प्रवृत्ति का है, की मौजूदगी की जांच की जाएगी। उक्त सुविधा 10 फरवरी 2015 को वीपीटी में संस्थापित और शुरू की गई थी।
- (ii) वीपीटी ने, ट्रेड से विचार-विमर्श कर, यह निष्कर्ष निकाला था कि ऐसी सुविधाओं के लिए विशिष्ट प्रभार प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित तथा अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे विशिष्ट प्रभार के बारे में ट्रेड को सूचित किया जा सके तथा इस सुविधा के लिए पत्तन उपयोगकर्ताओं से वसूली की जा सके जब उनके वाहन ईक्यू-7 गेट के माध्यम से गोदी क्षेत्र परिसर के भीतर तथा बाहर जाएं।

- (iii) संबद्ध ट्रेड द्वारा जब कभी ऐसी सेवा प्राप्त करने के लिए प्रभार वसूल करने के लिए, वीपीटी ने अस्थायी रूप से उक्त स्थान के माध्यम से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन के एक प्रवेश तथा निकासी के लिए अस्थायी रूप से रु0 63/- की दर से ऐसी सेवाओं के लिए प्रशुल्क निर्धारित किया था ताकि ऊपर यथा वर्णित संस्थापित उपकरण के माध्यम से रेडियोलॉजिकल का पता लगाया जा सके।

2.2. पत्तन ने 6 अप्रैल 2015 को ट्रेड के साथ हुई बैठक के कार्यवृत्त की प्रति प्रस्तुत की है। बैठक के कार्यवृत्त में प्रतिवेदित मुख्य बिन्दुओं को नीचे सारबद्ध किया गया है:-

- (i) ट्रेड ने वीपीटी से इस खाते पर कोई शुल्क वसूल नहीं करने का अनुरोध किया था क्योंकि वीपीटी उपयोक्ताओं को कोई सेवा प्रदान नहीं कर रहा है और इकाई मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षा कारणों से वीपीटी की अनिवार्य अपेक्षा की वजह से स्थापित की गई थी। ट्रेड ने कहा है कि यह लागत केवल वीपीटी को वहन करनी चाहिए और यह भी उल्लेख किया है कि इस उपकरण की खरीद तथा संस्थापन से पहले ट्रेड से विचार-विमर्श नहीं किया गया था।
- (ii) ट्रेड प्रतिनिधियों ने यह भी कहा है कि एक इकाई की लागत लगभग रु0 2.5 करोड़ है तथा वीपीटी को भविष्य में 2-3 इकाईयों की आवश्यकता पड़ सकती है तथा यह लागत ट्रेड द्वारा वहन नहीं की जा सकती।
- (iii) ट्रेड ने वीपीटी से प्रस्ताव वापिस लेने तथा यह मामला टीएमपी को भेजने का अनुरोध किया था। ट्रेड सर्वसम्मत रूप से प्रभारों की अदायगी करने के लिए सहमत था यदि रेडियोलॉजिकल डिटेक्शन इक्वूपमेंट के संस्थापन के लिए उपयोक्ता शुल्क के मामले में टीएमपी द्वारा अनुमोदित तथा निर्धारित किए जाते हैं।

2.3. रेडियोलॉजिकल उपकरण के साथ प्रचालित ईक्वू-7 गेट के माध्यम से गुजरने वाले वाहनों के लिए प्रभारित की जाने वाली दर दर्शाते हुए पत्तन द्वारा प्रस्तुत किया गया लागत पत्रक नीचे दिया गया है:

| क्र.सं. | विवरण | राशि रु. में |
|---------|--|---|
| I. | 2 रेडियोलॉजिकल डिटेक्शन इक्वूपमेंट की पूंजी लागत | 26164310 |
| II. | परिवर्तनीय लागत बिजली लागत (4050 वॉट प्रति घंटा/1000=4.05 केडब्ल्यूएच 4.05 केडब्ल्यूएच अर्थात् प्रति घंटे उपभोग की गई इकाईयां x 24 घंटे x 365 दिन x आर) एस.टी. प्रचालन तथा अनुरक्षण स्टाफ के वेतन तथा मजदूरी और एमजीए - कुल परिवर्तनीय लागत | 336686 2338122 1308216 3983024 |
| III. | निर्धारित लागत जी.सं. 30 में टीएमपी अधिसूचना के अनुसार 100 टन वैगन धर्म कांटे का सुविचारित मूल्यहास @ 13.91% पूंजी लागत पर 16 प्रतिशत की दर से नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (19536924*16%) कुल निर्धारित लागत कुल लागत (II + III) ईक्वू-7 गेट के माध्यम से गुजरने वाले संभावित वाहनों की सं. | 3639456 3125908 6765363 10748387 170644 |
| | प्रभार प्रति वाहन (एक प्रवेश तथा एक निकासी के लिए) | 63 |

2.4. इस परिप्रेक्ष्य में, पत्तन ने इस प्राधिकरण से वीपीटी में ऐसी सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए परिगणित लागत निर्धारण के अनुसार 10 फरवरी 2015 से दर अनुमोदित तथा अधिसूचित करने का अनुरोध किया है।

3. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, वीपीटी के प्रस्ताव दिनांक 4 जुलाई 2015 की प्रति संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित की गई थी। हमें हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्रा0 लि0 (वीसीटीपीएल) से ही टिप्पणियाँ प्राप्त हुई थीं। वीसीटीपीएल को इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं थी। हमें एचपीसीएल की टिप्पणियों पर वीपीटी से टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई थीं।

4. प्रस्ताव दिनांक 04 जुलाई 2015 की प्राथमिक संवीक्षा पर, वीपीटी से हमारे पत्र दिनांक 14 अक्टूबर 2015 द्वारा अनुरोध किया गया था कि कुछ बिन्दुओं पर सूचना/स्पष्टीकरण भेजें। तथापि, वीपीटी ने प्रतिसाद नहीं दिया था। हमारे पत्र दिनांक 14 अक्टूबर 2015 द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण निम्नलिखित हैं:-

I. सामान्य:

- (i) वीपीटी के प्रस्ताव में नहीं बताया गया है कि यह प्रशुल्क नीति, 2015 के अधीन दाखिल किया गया है जोकि 13 जनवरी 2015 से प्रभावी है। कृपया पुष्टि करें।

- (ii) प्रशुल्क नीति, 2015 के खंड 1.5 के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित संशोधित वर्किंग दिशानिर्देशों का खंड 5.7.1. नई सेवा/कार्गो, जिनके लिए दरमान में प्रशुल्क उपलब्ध नहीं है, के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु विभिन्न पद्धतियाँ विनिर्दिष्ट करता है। उक्त खंड के अनुसार, यदि निर्धारित विकल्पों पर आधारित प्रशुल्क का निर्धारण संभव नहीं हो तो महापत्तन न्यास पर्याप्त कारण देने के बाद लागत जमा 16 प्रतिशत प्रतिलालं सूत्र पर दर प्रस्तावित कर सकता है। वीपीटी स्पष्ट करे कि क्या पत्तन ने लागत जमा पद्धति पर प्रस्ताव दाखिल करने से पहले उक्त खंड में उल्लिखित विकल्पों का पता लगाया है।
- (iii) हालांकि वीपीटी के आवरण पत्र दिनांक 4 जुलाई 2015 में बताया गया है कि पत्तन, ट्रेड से विचार-विमर्श कर, ईक्यू-7 गेट के माध्यम से गोदी क्षेत्र के अन्दर और बाहर जाने वाले वाहनों के लिए विशिष्ट प्रभारों की वसूली करने के निष्कर्ष पर पहुंचा है, परन्तु ट्रेड के साथ वीपीटी द्वारा दिनांक 6 अप्रैल 2014 को की गई बैठक के कार्यवृत्त की प्रति में दर्ज किया गया है कि ट्रेड ने देखा है कि पत्तन को यह सेवा प्रदान करने की लागत वहन करनी चाहिए और इसलिए पत्तन से प्रस्ताव वापिस लेने तथा टीएएमपी को भेजने का अनुरोध किया गया था। वीपीटी बैठक के उक्त कार्यवृत्त में प्रतिवेदित विषय प्रस्ताव पर ट्रेड द्वारा उठाई गई आपत्ति पर टिप्पणी करे।
- (iv) प्रस्तावित दर अनुमोदित करते हुए बोर्ड अनुमोदन की प्रति भेजे।

II. पूंजी लागत:

- (i) उपकरण की पूंजी लागत रु 26,164,130/- है। तथापि, आरओसीई के परिकलन के लिए, परिसंपत्ति का निवल प्रखंड रु 19,536,924 सुविचारित किया गया है। प्रशुल्क की वैधता अवधि तीन वर्षों के लिए परिसंपत्ति का औसत लिखित मूल्य, रु 36,39,456 प्रतिवर्ष के मूल्यहास पर विचार करने के बाद आरओसीई परिकलन के लिए सुविचारित रु 19,536,924 की बजाय रु 18,88,85,398 होता है, प्रशुल्क नीति, 2015 के अनुसार प्रशुल्क अनुमोदित किया जाए। वीपीटी आरओसीई परिकलन उपयुक्ततः सही करे।
- (ii) कुल पूंजी लागत में रु 23,72,378/- का उत्पाद शुल्क तथा रु 1,99,635/- का सेवा कर शामिल है। इस संबंध में, पुष्टि करें कि उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर के मामले में सेवेट क्रेडिट उपलब्ध नहीं है। पुष्टि करें कि परिसंपत्ति रु 26,164,310 के लिए पूंजीकृत किया गया है। यदि सेवेट क्रेडिट उपलब्ध हो तो लागत विवरण सेवेट क्रेडिट को अलग रखते हुए उपयुक्ततः संशोधित किया जाए।

III. प्रचालन लागत:

- (i) 4.05 इकाईयां प्रति घंटा की दर से बिजली उपभोग का आधार भेजे। अनुमानन में सुविचारित बिजली की इकाई दर के समर्थन में अद्यतन बिजली बिल की प्रति भी भेजे।
- (क) वीपीटी ने "एस.टी." रूप में रु 23.88 लाख का अनुमान लगाया है। वीपीटी इस व्यय की प्रकृति और अनुमानों हेतु आधार स्पष्ट करे।
- (ख) रेडियोलॉजिकल इक्वूपमेंट (आर.ई.) के संस्थापन के लिए जारी किए गए कार्य आदेश के बारे में प्रस्ताव करते हुए प्रस्ताव के साथ संलग्न किए गए मुख्य अभियांत्रिक अभियंता पत्र दिनांक 2 फरवरी 2015 के अनुसार, यह देखा गया है कि कुछ अस्थायी अनुमान प्रथम 5 वर्षों (प्रथम वर्ष के बाद) और 10 वर्षों के लिए एएमसी हेतु भेजे गए हैं। वीपीटी से यह पुष्टि करने का अनुरोध किया गया था कि क्या प्रस्तावित प्रशुल्क पर पहुंचने के लिए लागत अनुमान एएमसी के अनुमानों पर विचार करते हैं। अनुमानों के समर्थन में कृपया कार्य आदेश की प्रति भेजे।
- (iii) (क) लागत विवरण में सुविचारित प्रचालन तथा अनुरक्षण स्टाफ के वेतन तथा मजदूरी हेतु गणना भेजे।
- (ख) लागत विवरण एमजीए दर्शाता है जो वेतन तथा मजदूरी के हिस्से के रूप में भी माना जाता है। इस गतिविधि में एमजीए के प्रभाजन के आधार का औचित्य बताएं। चूंकि एमजीए सामान्य संशोधन प्रस्ताव में पहले ही सुविचारित किया जा चुका है, वीपीटी पुष्टि करे कि इससे दोहराकरण नहीं होगा यदि वर्तमान प्रस्ताव में विचार किया जाता है।
- (iv) (क) पत्तन ने एक दूसरे मामले में वैगन धर्मकांटे के लिए सुविचारित 13.91 प्रतिशत की मूल्यहास दर का उल्लेख किया है। रेडियोलॉजिकल उपकरण हेतु मूल्यहास दर के प्रयोजन के लिए वैगन धर्म कांटे का उल्लेख करने की प्रासंगिकता स्पष्ट करें।
- (ख) पुष्टि करें कि सुविचारित मूल्यहास दर कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक पृष्ठ के सार के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 से ली गई प्रासंगिक मूल्यहास दर का संदर्भ दें।

5. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 16 अक्टूबर 2015 को वीपीटी परिसर में आयोजित की गई थी। वीपीटी ने अपने प्रस्ताव का पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया था। संयुक्त सुनवाई में, वीपीटी तथा उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशन ने अपने निवेदन रखे थे।

6.1. संयुक्त सुनवाई में यथा सहमत, वीपीटी से हमारे पत्र दिनांक 26 अक्टूबर 2015 द्वारा संयुक्त सुनवाई कार्यवाही से निकलने वाले निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाई करने का अनुरोध किया गया था:

- (i) संयुक्त सुनवाई में पेश किए गए पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण की प्रति भेजे।
- (ii) संयुक्त सुनवाई में, उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशनों ने दरमानों के सामान्य संशोधन, जोकि देय है, हेतु प्रस्ताव भेजने के समय किसी अन्य प्रासंगिक प्रशुल्क मद के साथ प्रस्तावित प्रशुल्क को आमेलित करने का अनुरोध किया था। वीपीटी उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशनों के सुझावों की जांच करे तथा 15 दिनों के भीतर अर्थात् 31 मार्च 2015 तक प्रतिसाद दे।

6.2. संयुक्त सुनवाई में उपस्थित उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशनों ने बताया था कि ईक्यू-7 गेट में संस्थापित रेडियोलॉजिकल उपकरण सुविधा हेतु प्रभारों की वसूली के निर्धारण हेतु वीपीटी द्वारा दाखिल किया गया प्रस्ताव उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। हमारा कार्यालय अभिलेख दर्शाता है कि उक्त प्रस्ताव हमारे पत्र दिनांक 17 जुलाई 2015

द्वारा टिप्पणियों के लिए सभी संबंधितों को अग्रेषित किया गया था। तथापि, संयुक्त सुनवाई में यथा निर्णीत, वीपीटी प्रस्ताव दिनांक 4 जुलाई 2015 की प्रति हमारे पत्र दिनांक 26 अक्टूबर 2015 द्वारा एक बार दोबारा उन उपयोक्ताओं/संगठन निकायों को परिचालित की गई थी जो संयुक्त सुनवाई में उपस्थित थे और उन्हें 30 अक्टूबर 2015 तक अपनी टिप्पणियां वीपीटी एवं इस प्राधिकरण को भेजने के लिए कहा गया था। वीपीटी से हमारे पत्र दिनांक 26 अक्टूबर 2015 द्वारा उसके बाद सात दिनों के भीतर अपना प्रतिसाद भेजने का अनुरोध भी किया गया था।

7. संयुक्त सुनवाई के बाद, विशाखापत्तनम स्टीवडोर्स एसोसिएशन (वीएसए) ने विषय प्रस्ताव पर अपने पत्र दिनांक 18 नवम्बर 2015 द्वारा अपनी टिप्पणियां भी भेजी थीं। किसी भी अन्य उपयोक्ता/उपयोक्ता एसोसिएशन ने कोई टिप्पणियां नहीं भेजी थीं बावजूद इसके कि हमारे पत्र दिनांक 26 अक्टूबर 2015 द्वारा एक बार दोबारा वीपीटी प्रस्ताव अग्रेषित किया गया था। वीपीटी से यह अनुरोध करते हुए प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में वीपीटी को वीएसए की टिप्पणियां अग्रेषित की गई थीं कि वीएसए द्वारा की गई टिप्पणियों पर अपने विचार तत्काल भेजें।

8.1. कार्रवाई के प्रथम बिन्दु के संबंध में, वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 5 नवम्बर 2015 द्वारा संयुक्त सुनवाई में दिए गए पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण की प्रति भेजी थी।

8.2. वीपीटी ने अनुस्मारकों दिनांक 6 नवम्बर 2015 और 3 दिसम्बर 2015 के बाजूद संयुक्त सुनवाई कार्यवाही से आने वाले कार्रवाई के दूसरे बिन्दु पर प्रतिसाद नहीं दिया था। तथापि, वीपीटी ने संयुक्त सुनवाई की कार्रवाई के दूसरे बिन्दु का उल्लेख करते हुए, 30 दिसम्बर 2015 को दाखिल किए गए अपने सामान्य संशोधन प्रस्ताव में एक दर का प्रस्ताव किया था जिसके बारे में अनुवर्ती अनुच्छेदों में बताया गया है।

9. इस मामले में विचार-विमर्श से संबंधित कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त हुई टिप्पणियों तथा संबद्ध पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग-से भेजा जाएगा। ये व्योरे हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

10.1. जैसाकि पहले बताया गया है, वीपीटी से दरमान के सामान्य संशोधन, जोकि पहले से देय है, हेतु उसके प्रस्ताव में इस प्रशुल्क मद को आमेलित करने के लिए उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशन के सुझाव की जांच करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि वीपीटी ने मौजूदा प्रस्ताव में कार्रवाई के इस विशिष्ट बिन्दु पर कोई प्रतिसाद नहीं दिया था, यहां पर उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वीपीटी ने अपने पत्र सं. एफए/लागत/एसओआर/211 दिनांक 30 दिसम्बर 2015 द्वारा अपने दरमान (एसओआर) के सामान्य संशोधन हेतु अपना प्रस्ताव दाखिल किया था। उक्त प्रस्ताव में, पत्तन ने बताया है कि दरमान के सामान्य संशोधन हेतु प्रस्ताव भेजने के समय किसी अन्य प्रासंगिक प्रशुल्क मद के साथ रेडियोलॉजिकल उपकरण सुविधा हेतु प्रस्तावित प्रशुल्क आमेलित करने के लिए 16 अक्टूबर 2015 को हुई संयुक्त सुनवाई में उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशनों द्वारा किए गए अनुरोध और उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशन के सुझाव की जांच करने के लिए इस प्राधिकरण को किए गए अनुरोध के अनुसार, पत्तन ने प्रशुल्क नीति, 2015 के अधीन अपना सामान्य संशोधन प्रस्ताव दाखिल किया था। इसने यहां पर अनुसूची 4.1 में निर्धारित घाटशुल्क दर के अलावा रेडियोलॉजिकल उपकरण के संस्थापन के लिए 10 वर्षों की अवधि के लिए शुष्क बल्क तथा ब्रेक बल्क कार्गो पर 0.38 पैसा प्रति टन वसूल करने का प्रस्ताव किया था। पत्तन ने प्रस्तावित दर के समर्थन में विस्तृत गणना भेजी थी। वीपीटी द्वारा दाखिल किए गए मसौदा प्रस्तावित दरमान से यह देखा गया है कि पत्तन ने इसके लिए अनुसूची 4.1. - घाटशुल्क प्रभार के अधीन एक टिप्पणी शामिल की है।

10.2. चूंकि वीपीटी सामान्य संशोधन प्रस्ताव में रेडियोलॉजिकल उपकरण हेतु प्रशुल्क पहले ही प्रस्तावित कर चुका है, इसलिए इस प्राधिकरण को सामान्य संशोधन प्रस्ताव के साथ इस प्रशुल्क मद पर कार्यवाही करना उपयुक्त लगता है।

11. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण ईक्यू-7 गेट में अवसंरचनात्मक रूप में संस्थापित रेडियोलॉजिकल उपकरण सुविधा हेतु प्रभारों की वसूली के निर्धारण हेतु वीपीटी द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव दिनांक 4 जुलाई 2015 को बन्द करने का निर्णय लेता है। रेडियोलॉजिकल उपकरण हेतु प्रशुल्क निर्धारण वीपीटी द्वारा दाखिल किए गए सामान्य संशोधन प्रस्ताव, जिसपर अलग से कार्यवाही की जा रही है, के साथ विचार किया जाएगा।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन—III/4/असा./143/16(27)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 12th April, 2016

No. TAMP/54/2015-VPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Visakhapatnam Port Trust (VPT) for fixation of charges for Radiological equipment facility installed at EQ-7 gate as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/54/2015-VPT

Visakhapatnam Port Trust

Applicant

QUORUM:

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 30th day of March 2016)

This case relates to the proposal dated 4 July 2015 received from the Visakhapatnam Port Trust (VPT) for fixation of charges for Radiological equipment facility installed at EQ-7 gate.

2.1. The highlights of the proposal submitted by VPT are summarized below:

- (i) The Visakhapatnam Port has installed mechanical facility (equipment) for carrying out radiological detection at EQ-7 gate inside Dock area premises, wherein the vehicles plying in and out of Dock area through entry/exit point at the above said location will be scrutinized for presence of radiological element, if any, which is hazardous in nature. The said facility was installed and commissioned at VPT on 10 February 2015.
- (ii) VPT, in consultation with trade, has come to conclusion that specific charge for such facilities needs to be approved and notified by Authority so as to inform the Trade regarding such specific charge and also to levy the same on the Port users for this facility as and when their vehicles ply in and out of Dock area premises through EQ-7 gate.
- (iii) To levy charge for such service as and when availed by the trade concerned, VPT has tentatively fixed the tariff to be levied for such services at ₹63/- provisionally for one entry and exit of each vehicle passing through the said location so as to undergo radiological detection through installed equipment as described above.

2.2. The port has submitted a copy of the minutes of the meeting held with trade on 6th April 2015. The main points recorded in the minutes of the meeting are summarised below:

- (i) Trade requested VPT not to charge any fee on this account since VPT is not rendering any service to the users and that the unit was set up due to mandatory requirement of VPT for security reasons as per the Ministry's Guidelines. Trade stated that the cost has to be borne by VPT only and further mentioned that the Trade was not consulted before procurement and installation of the equipment.
- (ii) The Trade representatives also stated that the cost of one unit is about ₹2.5 crores and VPT may require 2-3 units in future and this cost cannot be borne by the Trade.
- (iii) Trade has requested VPT to withdraw the proposal and refer the matter to the TAMP. The trade unanimously agreed to pay the charges if approved and fixed by the TAMP in respect of the user fee for installation of Radiological Detection Equipment.

2.3. A Cost Sheet submitted by the port showing the rate to be charged for the vehicles passing through EQ-7 gate operated with radiological equipment is given below:

| Sl. No. | Description | Amount in ₹ |
|---------|--|-------------|
| I. | Capital cost of 2 Radiological Detection Equipment | 26164310 |
| II. | VARIABLE COST | |
| | Power Cost (4050 Watts per hour/1000=4.05 KWHrs 4.05 KWH i.e. per hour units consumed x 24 hrs x 365 days x R) | 336686 |
| | S. T | 2338122 |
| | of Salaries and wages of operating and maintenance staff and MGA- | 1308216 |
| | TOTAL VARIABLE COST | 3983024 |
| III. | FIXED COST | |
| | Depreciation considered as per TAMP notification in G.No.30 of 100 Ton Wagon Weigh Bridge @ 13.91% | 3639456 |
| | Return on Capital Employed @ 16% on Capital Cost (19536924*16%) | 3125908 |
| | TOTAL FIXED COST | 6765363 |
| | TOTAL COST (II + III) | 10748387 |
| | No. of vehicles expected to pass through EQ-7 gate | 170644 |
| | Charges per vehicle (For one entry and one exit) | 63 |

2.4. In this backdrop, the port has requested this Authority to approve and notify the rate as per costing worked out for providing such services at VPT w.e.f.10 February 2015.

3. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the proposal of VPT dated 4 July 2015 was forwarded to the concerned users/user organisations seeking their comments. We have received comments only from Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) and Visakha Container Terminal Pvt. Ltd. (VCTPL). The VCTPL has no objection to the proposal of VPT. We have not received comments from the VPT on the comments HPCL.

4. On preliminary scrutiny of the proposal dated 04 July 2015, the VPT was requested vide our letter dated 14 October 2015 to furnish information/clarifications on a few points. The VPT has, however, not responded. The information/clarifications sought vide our letter dated 14 October 2015 are as follows:

I. General:

- (i) The proposal of the VPT does not state that it is filed under Tariff Policy, 2015 which is effective from 13 January 2015. Please confirm.
- (ii) Clause 5.7.1. of the revised Working Guidelines notified by the Authority in compliance with Clause 1.5. of the Tariff Policy 2015, stipulates the various methods for fixation of tariff for a new service/cargo for which tariff is not available in the SOR. As per the said Clause, if the determination of tariff based on prescribed options is not possible then the Major Port Trust after giving sufficient reasons may propose rate on cost plus 16% return formula. The VPT to clarify whether the port has explored the options mentioned in the said Clause before filing up the proposal on cost plus method.
- (iii) Though the covering letter of the VPT dated 4 July 2015 states that the port has, in consultation with the trade, come to the conclusion for levy of specific charges for vehicle plying in and out of dock area through EQ-7 gate, the copy of the minutes of the meeting dated 6 April 2014 by the VPT with the trade records that the trade has viewed that port should bear the cost of rendering this service and hence has requested the port to withdraw the proposal and refer to TAMP. The VPT to comment upon the objection raised by the trade on the subject proposal recorded in the said minutes of the meeting.
- (iv) Furnish a copy of the Board approval approving the proposed rate.

II. Capital Cost:

- (i) The capital cost of the equipment is ₹26,164,310/-. However, for computation of ROCE, the net block of asset is considered at ₹19,536,924. The average written down value of the asset for three years being the validity of the tariff to be approved as per the Tariff Policy, 2015, after considering the depreciation of ₹36,39,456 per annum comes to ₹18,88,85,398 instead of ₹19,536,924 considered for ROCE computation. The VPT to suitably correct the ROCE computation.
- (ii) The total capital cost includes Excise duty of ₹23,72,378/- and Service Tax of ₹1,99,635/-. In this regard, to confirm that the cenvat credit with respect to Excise duty and Service Tax is not availed. Confirm the asset is capitalised for ₹26,164,310. If cenvat credit is available, the cost statement may be suitably modified excluding the cenvat credit.

III. Operating Cost:

- (i) Furnish the basis of power consumption at 4.05 units per hour. Also, furnish a copy of latest electricity bill in support of unit rate of power considered in the estimation.
- (ii)
 - (a) The VPT has estimated ₹23.38 lakhs as "S.T". VPT to clarify the nature of this expenditure and basis for the estimates.
 - (b) As per the Chief Mechanical Engineer letter dated 2 February 2015 attached to the proposal proposing about the work order issued for installation of Radiological Equipment (R.E.), it is seen that some tentative estimates are furnished for AMC for first 5 years (after the first year) and for 10 years. The VPT requested to confirm whether cost estimates for arriving at the proposed tariff considers the estimates of AMC. Copy of the work order please be furnished in support of the estimates.
- (iii)
 - (a) Furnish the working for the salary & wages of operating and maintenance staff considered in the cost statement.
 - (b) The cost statement shows MGA is also considered as part of salaries and wages. The basis of apportionment of MGA to this activity to be justified. Since MGA was already considered in general revision proposal, the VPT to confirm that it will not lead to duplication if considered in the current proposal.

- (iv) (a) The port has referred to the depreciation rate of 13.91% considered for wagon weigh bridge in one another case. Clarify the relevance of referring to wagon weigh bridge for the purpose of depreciation rate for radiological equipment.
- (b) Confirm the depreciation rate considered is as per the Companies Act 2013. Also, give reference to the relevant depreciation rate taken from the Companies Act 2013 substantiated with the extract of the relevant page of the Companies Act, 2013.

5. A joint hearing in this case was held on 16 October 2015 at the VPT premises. The VPT made a power point presentation of its proposal. At the joint hearing, the VPT and users/user association have made their submissions.

6.1. As agreed at the joint hearing, the VPT was requested vide our letter dated 26 October 2015 to take action on the following points arising out of joint hearing proceedings:

- (i) Furnish a copy of power point presentation made at the joint hearing.
- (ii) At the joint hearing, the users/users associations requested to merge the proposed tariff with any other relevant tariff item while sending proposal for general revision of Scale of Rates, which is due. The VPT to examine the suggestion of the users/user associations and respond within 15 days i.e. by 31 October 2015.

6.2. The users/user associations present at the joint hearing stated that they have not received the proposal filed by the VPT for fixation of levy charges for Radiological Equipment Facility installed at EQ-7 gate. Our office records show that the said proposal was forwarded to all concerned for comments vide our letter dated 17 July 2015. However, as decided at the joint hearing a copy of the VPT proposal dated 4 July 2015 was once again circulated to the users/organisation bodies who were present at the joint hearing vide our letter dated 26 October 2015 seeking their comments latest by 30 October 2015 to VPT as well as this Authority. The VPT was also requested to furnish its response within seven days thereafter vide our letter dated 26 October 2015.

7. After the joint hearing, the Visakhapatnam Stevedores Association (VSA) has furnished its comments vide its letter dated 18 November 2015 on the subject proposal. None of the other users/user association have furnished any comments despite forwarding the VPT proposal once again vide our letter dated 26 October 2015. The comments of VSA was forwarded to VPT as feedback information requesting the VPT to furnish its views on the comments made by VSA immediately.

8.1. As regards the first point of action, the VPT vide its letter dated 5 November 2015 has furnished the copy of power point presentation made at the joint hearing.

8.2. The VPT has not responded to the second point of action flowing from the joint hearing proceedings despite reminders dated 6 November 2015 and 3 December 2015. The VPT has, however, referring to the second point of action of the joint hearing, proposed a rate in its general revision proposal filed on 30 December 2015 which is brought out in the subsequent paragraphs.

9. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

10.1 As brought out earlier, VPT was requested to examine the suggestion of users/user association to merge this tariff item in its proposal for general revision of SOR, which is already due. Though the VPT has not responded on this specific point of action in the current proposal, it is relevant to state that the VPT vide its letter No.FA/COST/SOR/211 dated 30 December, 2015 has filed its proposal for general revision of its Sale of Rates (SOR). In the said proposal, the port has stated that as per the request made by the users/users association in the joint hearing held on 16 October 2015 to merge the proposed tariff for radiological equipment facility with any other relevant tariff item while sending proposal for general revision of SOR and with the request of this Authority to examine the suggestion of the users/user association, the Port has filed its General Revision proposal under Tariff Policy 2015. It has therein proposed to collect 0.38 paise per ton on dry bulk and break bulk cargoes for a period of 10 years towards installation of radiological equipment in addition to the wharfage rate prescribed in schedule 4.1. The port has furnished detailed working in support of the proposed rate. It is seen from the draft proposed SOR filed by the VPT that the port has inserted a note under Schedule 4.1.- Wharfage charges to this effect.

10.2. Since the VPT has already proposed tariff for radiological equipment in the general revision proposal, this Authority finds it appropriate to deal with this tariff item along with the general revision proposal.

11. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority decides to close the proposal dated 4 July 2015 filed by VPT for fixation of levy charges for Radiological equipment facility installed at EQ-7 gate as infructuous. The tariff determination for radiological equipment will be considered along with the general revision proposal filed by the VPT which is being processed separately.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT-III/4/Exty./143/16(27)]